समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Tuesday, 22 September 2026

महाराष्ट्र एंटी-कन्वर्जन बिल को लेकर सियासत तेज, शिवसेना (UBT) ने भी दिया समर्थन

Sanket Morankar Published on 17 Mar 2026

महाराष्ट्र में प्रस्तावित एंटी-कन्वर्जन (धर्म परिवर्तन विरोधी) बिल को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। इस मुद्दे पर जहां सत्तारूढ़ और विपक्षी दल आमने-सामने हैं, वहीं शिवसेना (UBT) के रुख ने राजनीतिक समीकरणों को नया मोड़ दे दिया है।

शिवसेना (UBT) द्वारा इस बिल को समर्थन दिए जाने को हिंदुत्व की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी का यह रुख राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब विभिन्न दल अपनी वैचारिक स्थिति स्पष्ट करने में लगे हैं।

हिंदुत्व के मुद्दे पर एकजुटता ?

शिवसेना (UBT) के इस समर्थन को हिंदुत्व की विचारधारा के संदर्भ में देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम पार्टी की पारंपरिक पहचान को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है।

हालांकि, इस समर्थन के पीछे राजनीतिक रणनीति भी मानी जा रही है, क्योंकि राज्य में आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए सभी दल अपने-अपने वोटबैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं।

फडणवीस और शिंदे की प्रतिक्रिया

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री Devendra Fadnavis ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि धर्म परिवर्तन के खिलाफ सख्त कानून समय की मांग है और इससे सामाजिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी।

वहीं मुख्यमंत्री Eknath Shinde ने भी इस बिल का समर्थन करते हुए कहा कि राज्य सरकार समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार के जबरन या प्रलोभन देकर किए जाने वाले धर्म परिवर्तन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

विपक्ष की अलग राय

जहां एक ओर कुछ दल इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, वहीं विपक्ष के कुछ नेताओं ने इसे लेकर चिंता भी जताई है। उनका कहना है कि इस तरह के कानूनों का दुरुपयोग हो सकता है और इससे सामाजिक तनाव बढ़ने की आशंका है।

क्या है एंटी-कन्वर्जन बिल ?

एंटी-कन्वर्जन बिल का उद्देश्य जबरन, धोखे या लालच देकर किए जाने वाले धर्म परिवर्तन को रोकना है। देश के कई राज्यों में पहले से ही इस तरह के कानून लागू हैं, और अब महाराष्ट्र में भी इसे लागू करने की चर्चा तेज हो गई है।

आगे क्या ?

महाराष्ट्र में इस बिल को लेकर आने वाले दिनों में और भी राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिल सकती है। शिवसेना (UBT) के समर्थन के बाद यह मुद्दा और भी अहम हो गया है, क्योंकि इससे राज्य की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं।

फिलहाल, सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार इस बिल को कब और किस रूप में पेश करती है, और विधानसभा में इसे कितना समर्थन मिलता है।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Sanket Morankar, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.